हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 172 लखनऊ मंगलवार 17 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

"फियर जोन" से "फेथ जोन" में परिवर्तित हुआ है उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री

न कर्फ्यू है, न दंगा है बल्कि यूपी में सब चंगा है : योगी

पिछले नौ वर्षों में सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीयत और निर्णायक नेतृत्व से बदली शासन–प्रशासन की दिशा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सोमवार को विधान परिषद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रखे विचार

राज्यपाल के प्रति अभद्र व्यवहार को लेकर विपक्ष पर किया करारा प्रहार

सीएम बोले, आज प्रदेश कर्फ्यू कल्चर से कानून के राज और अविश्वास से आत्मविश्वास तक पहुंचा

डबल इंजन सरकार की नीति से यूपी बना निवेश, नवाचार और पारदर्शिता का मॉडल

प्रयागराज में श्रध्दालुओं की रिकॉर्ड भागीदारी सुरक्षा और सुशासन पर बढ़े विश्वास का प्रमाण

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सोमवार को विधान परिषद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदन में राज्यपाल के प्रति अभद्र और अशिष्ट व्यवहार करने पर विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही प्रभावी कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि न कर्फ्यू है, न दंगा है, बल्कि यूपी में सब चंगा है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके बावजूद राज्यपाल पर प्रतिपक्ष द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। यह न केवल लोकतंत्र को कमज़ोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े सभी प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। साथ ही संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें। उनके प्रति कोई ऐसा आचरण न करें, जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे, लेकिन प्रतिपक्ष से इसकी अपेक्षा करना व्यर्थ है।

प्रदेश की जनता को पहले ही मिलना चाहिये था कानून का राज

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्यपाल एक अनुभवी राजनेता होने के साथ आज प्रदेश सरकार की संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व सभी को प्रदान कर रही हैं। उनके प्रति अभद्र व्यवहार समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच और प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। पिछले नौ वर्ष में प्रदेश

ने एक अपनी यात्रा तय की है। यह यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन, कर्फ्यू से कानून के राज, उपद्रव से उत्सव की यात्रा, समस्या से समाधान और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। इस यात्रा को देश और दुनिया स्वीकार करती है। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। यह अधिकार प्रदेश की 25 करोड़ जनता को पहले ही मिलना चाहिये था लेकिन अपने संकुचित एजेंडे को लेकर चलने वाली सरकारों ने प्रदेश के भविष्य और जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया। प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया। इस दौरान कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उत्तर प्रदेश को भारत के शाश्वत मूल्यों की आधारभूमि माना जाता है, उसमें किस प्रकार की अव्यवस्था थी, यह हम सबने देखा है। वहीं डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ़ नीयत, सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता से आज उत्तर प्रदेश ने बॉटलनेक से देश की अर्थव्यवस्था का ब्रेकथॉट बनाने में सफलता प्राप्त की है।

दुनिया के सामने टेक्नोलॉजी, भरोसे और परिवर्तन के समन्वित मॉडल के रूप में उभरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी रेवन्यू सरप्लस और उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी यात्रा को लेकर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े एआई इंपेक्ट समिट का उद्घाटन किया है। यह पांच दिनों तक देश और दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में चलेगा। इस समय जब दुनिया तेजी से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, तब भारत भी इस दिशा में मजबूत और दूरदर्शी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। देश न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन योजना के साथ कार्य कर रहा है। इसी राष्ट्रीय सोच के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी पिछले साढ़े आठ से पौने नौ वर्षों में खुद को परिवर्तन की आधारभूमि के रूप में स्थापित किया है। प्रदेश में आए इस व्यापक बदलाव को "टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन" की त्रिवेणी के रूप में देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के सामने टेक्नोलॉजी, भरोसे और परिवर्तन के समन्वित मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। यह त्रिवेणी केवल एक नारा नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली और विकास की दिशा का प्रतीक बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की ही धरती पर प्रयागराज स्थित है जिसकी पहचान मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी से है। उसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक को आधुनिक संदर्भ में नया रूप देते हुए उत्तर प्रदेश ने "टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन" की नई त्रिवेणी को विकास के केंद्र में स्थापित किया है। यह नई त्रिवेणी प्रदेश की प्रगति, पारदर्शिता और जनविश्वास की आधारशिला बन चुकी है।

नीतिगत उदासीनता और विकास विरोधी सोच के माहौल को हमने बदला

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में नीतिगत उदासीनता, प्रशासनिक शिथिलता और विकास

विरोधी सोच का जो माहौल था, उसे बीते वर्षों में पूरी तरह बदलने का प्रयास किया गया। अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीति और शुद्ध नीयत के माध्यम से शासन–प्रशासन को एक नई दिशा देने का कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार के कार्यों का प्रभाव भी प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से लेकर रोजगार सृजन के व्यापक अभियानों तक, हर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश का वातावरण सुदृढ़ हुआ है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न माध्यमों से प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है।

_मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली प्रदेश की नियति बन चुकी थी। "वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया" जैसी स्थिति ने उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। कानून चंद हाथों की जागीर बन गया था और कर्फ्यू व दंगे आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के बजाय आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटियां सुरक्षित थीं और न व्यापारी। उस दौर में प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता के पर्याय के रूप में देखी जाती थी। वहीं वर्ष 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त

उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश में बदल चुका है। अब राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ है। विकास की पहली शर्त 'रूल ऑफ लॉ' है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने मजबूती से काम किया। रिकॉर्ड स्तर पर पुलिस भर्तियां की गईं, महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया और युवाओं के लिए नई–नई योजनाएं शुरू की गईं। मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी विशेष कार्य किया गया। सुदृढ़ कानून–व्यवस्था से उत्तर प्रदेश अब "फियर जोन" से "फेथ जोन" में परिवर्तित हो गया है। अब यहां भय का नहीं बल्कि आस्था का वातावरण है। लोग सुरक्षा और व्यवस्था पर विश्वास के साथ प्रदेश में आ रहे हैं। "कर्फ्यू कल्चर" की जगह "जीरो टॉलरेंस कल्चर" ने नई पहचान दी है। दंगों की जगह अब फेस्टिव और टेंपल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी तेजी से विकसित हो रही है। जो प्रदेश पहले दंगों और अव्यवस्था के कारण भय की स्थिति में था, वहां अब उत्सव और आस्था का वातावरण दिखाई देता है।

वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुम्भ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन हुआ। प्रयागराज में माघ मेला भी संपन्न हुआ। पहले माघ मेले में मुख्य रूप से कल्पवासी आते थे, जो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक एक महीने के लिए प्रवास करते थे और श्रद्धालुओं की संख्या कुछ लाख तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। श्रद्धालुओं की यह अभूतपूर्व भागीदारी केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि व्यवस्था और सुरक्षा के प्रति उनके विश्वास का भी प्रमाण है। भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यहां अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, मथुरा–वृंदावन की भक्ति और प्रयागराज की समरसता त्रिवेणी, कुम्भ और महाकुम्भ जैसे आयोजनों में स्पष्ट दिखाई देती है। इन आयोजनों ने प्रदेश की नई पहचान को सुदृढ़ किया है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। अब हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, बल्कि "यूपी में सब चंगा है।"

संक्षिप्त समाचार

सबरीमाला में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में नौ जजों की पीठ गठित, सात अप्रैल से होगी सुनवाई

एजेंसी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 9–न्यायाधीशों की बेंच 7 अप्रैल से धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के भेदभाव के मामलों पर सुनवाई शुरू करेगी। इस मामले में प्रमुख रूप से केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें 14 मार्च तक जमा करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करते हैं। बेंच में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील परमेश्वर और शिवम सिंह को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है, ताकि न्यायालय को आवश्यक मार्गदर्शन और पक्षों की दलीलों का विश्लेषण प्रदान किया जा सके। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सुनवाई 22 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करने वाले पक्षों के लिए कृष्ण कुमार सिंह को नोडल काउंसल नियुक्त किया गया है, जबकि फैसले का विरोध करने वालों के लिए शश्वती परी को नोडल काउंसल बनाया गया। यह मुद्दा इसलिए फिर सामने आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 2018 के फैसले से जुड़े रिव्यू और रिट याचिकाओं पर विचार करने वाला है।

एयरो इंजन पर राजनाथ सिंह बोले–हमें पांच साल में वो करना है, जो दूसरे देश 20 साल में करते हैं

एजेंसी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अगली पीढ़ी के एयरो इंजन के विकास में तेजी लाने की अपील की और कहा कि देश के पास समय कम है। अगर किसी इंजन के विकास में आमतौर पर 25 साल लगते हैं, तो यह मानकर चलें कि 20 साल बीत चुके हैं और अब हमारे पास केवल पांच साल बचे हैं। हमें 5 साल में वो कर दिखाना है, जो दूसरे देश 20 साल में करते हैं रक्षामंत्री ने विशेषज्ञों व शोधकर्ताओं से कहा, अगर किसी इंजन को विकसित करने में 25 साल लग रहे हैं, तो भारत की मौजूदा स्थिति , हमारी रणनीतिक जरूरत और हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी हैं कि आप मानकर चलिए कि आपके 20 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ पांच साल ही आपके पास बचे हैं। यह कोई अचरज वाली बात नहीं है, यह एक चुनौती है। हमें पांच साल में वो कर दिखाना है, जो दूसरे देश 20 साल में करते हैं। इसी में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य की तरफ भी देखना होगा। हम सिर्फ 5वीं पीढ़ी के इंजन तक सीमित नहीं रह सकते। छठी पीढ़ी की एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास भी हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा। उस पर रिसर्च , समय की मांग है। जैसे–जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग और न्यू मटीरियल का प्रयोग बढ़ रहा है, हमें उनमें आगे रहना होगा। उन्होंने यहां मौजूद वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं से कहा कि आप इंग्लैंड के साथ एयरो इंजन विकसित करने के लिए संयुक्त अध्ययन कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा, फ्रांस के साथ भी, एयरो इंजन के लिए, हम नेशनल एयरो इंजन मिशन के तहत प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। फ्रांस और यूके, दोनों ही देश एयरो इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहे हैं। उनके साथ यह समझौता हमें न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका देगा बल्कि उन चुनौतियों को भी समझने में सहायता करेगा, जिनका हमने पिछले दशकों में सामना किया है। रक्षामंत्री ने कहा कि जब हम सरकार में आए, तो हमने आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए। रक्षा क्षेत्र में भी,आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के हमने कई प्रयास किए। उन्होंने कहा, "मैंने अपने लगभग 7

साल के कार्यकाल में, अपना पूरा प्रयास किया कि हम एयरो इंजन के विकास को प्राथमिकता पर रखें और ऐसा हमने किया भी। आज की वैश्विक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, इस तरह की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है, यह मैं समझता हूं कि बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने साफ देखा, कि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी ने, हमारे देश में बने हथियारों ने, हमारी फोर्स का कितना सहयोग किया। चाहे संचार सिस्टम हो, सर्विलांस के साधन हों, या फिर अटैक करने वाले हथियार, सबमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी की झलक साफ दिखी।" उन्होंने कहा कि इससे सेना का मनोबल और बढ़ा व देश के लोगों को भी गर्व हुआ। अब जैसे–जैसे समय बदल रहा है, चुनौतियां बदल रही हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम स्वदेशी तौर–तरीकों पर और ज्यादा फोकस करें और हमारी फोर्स को विश्व स्तरीय प्रणालियां और उपकरण उपलब्ध कराएं। रक्षामंत्री ने कहा कि आज भारत के सामने बहुत सारे अवसर हैं। हमें उन अवसरों को भुनाने की जरूरत है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड समझौते का भी जिक्र किया। ट्रेड एग्रीमेंट भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की स्वीकार्यता उन्होंने बताया कि यह समझौता 18 वर्षों से नहीं हो पा रहा था, वह अब पूरा हो गया। यह ट्रेड एग्रीमेंट भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की स्वीकार्यता भी है। रक्षामंत्री ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही, वह ग्रीक के रक्षामंत्री से मिले थे। उस बातचीत के दौरान, उन्हें एक बहुत सुखद सरप्राइज मिला। दरअसल इस मुलाकात में ग्रीक के रक्षामंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि वह भारत को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की तरह देख रहे हैं। उनकी नजर में भारत अब कोई साधारण राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर है।

प्रदेश की आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जाएगा मानदेय

सीएम योगी ने सदन में की घोषणा

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा में मुख्यमंत्री ने हाल ही में निराश्रित व वृद्धा अवस्था पेंशन की घोषणा की चर्चा करते हुए कहा कि हम आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के लिए भी सरकार काम कर रही है। हाल ही में शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा हुई है। एक अप्रैल से इसका लाभ भी मिलने लगेगा। इसमें पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा निरूशुल्क उपलब्ध होगी। हमारी सरकार तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण कर रही है। हमने छह करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। इससे पहले सीएम ने कहा कि पहले कहा जाता था कि देख सपाई, बिटिया घबराई। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब बेटियां रात की शिफ्ट में भी काम करके सुकून से घर जाती हैं। उन्होंने कहा कि विकास की पहली शर्त 'रूल ऑफ लॉ' है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने मजबूती से काम किया। रिकॉर्ड स्तर पर पुलिस भर्तियां की गईं, महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया। युवाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की गईं। मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी विशेष कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून–व्यवस्था से उत्तर प्रदेश अब फियर जोन से फेथ जोन में बदला है। अब यहां भय का नहीं बल्कि आस्था का वातावरण है। लोग सुरक्षा और व्यवस्था पर विश्वास के साथ प्रदेश में आ रहे हैं। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने नई पहचान दी है। दंगों की जगह अब फेस्टिवल और टेंपल आधारित अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। जो प्रदेश पहले दंगों और अव्यवस्था के कारण भय की स्थिति

में था, वहां अब उत्सव और आस्था का वातावरण दिखाई देता है। यूपी उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है।

संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहा विपक्ष

सीएम ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है। समाज को आपस में लड़ाने, आस्था का अपमान, गुंडागर्दी व अराजकता को बढ़ाने के साथ संवैधानिक मूल्य पर भी प्रहार करने में नहीं चूक रहे हैं। सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ और अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर रहे हैं, यह शोभा नहीं देता। यह संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना, मजाक, अपमान है। अगर हम संविधान की शपथ लेते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान दें। उन्होंने बताया कि एसआईआरए में 2.88 करोड़ से अधिक लोग अनुपस्थित, मृत या शिफ्टिंग हैं। सपा इन्हें जबर्दस्ती वोट बनाकर फर्जी पोलिंग करती थी। आज वो चिल्ला रही है कि फॉर्म–7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। सीएम ने आयोग द्वारा बनाई गई फॉर्म–6, फॉर्म–7 व फॉर्म–8 की व्यवस्था की उपयोगिता बताई।

बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से अधिक थी, जो अब घटकर 2.24 प्रतिशत तक पहुंची

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने नौ वर्षों में पर्यटन, हॉस्पिटिलिटी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों तक सीमित न रहकर नई तकनीकों और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश ऑटोमेशन और डाटा आधारित निर्णय प्रणाली को अपनाते हुए एआई रोबोटिक्स, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में एक साथ प्रगति कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। हाल ही में लखनऊ में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस क्षेत्र से जुड़े कई नए निवेश प्रस्ताव भी लगातार आ रहे हैं। आज देश में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देश में खरीदे जा रहे हैं, उनमें से 19 फीसदी से अधिक हिस्सा यूपी का है। वहीं, तिपहिया वाहनों में 40 फीसदी से अधिक भागीदारी है। फेम–1 और फेम–2 के प्रमुख लाभार्थी यूपी के हैं। एक्सप्रेस कॉरिडोर पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन यूपी में हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदलती पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार युवा शक्ति है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश का युवा तेजी के साथ अपनी एक नई धमक और पहचान बना रहा है। आज प्रदेश में 20,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न हैं, आज प्रदेश के युवा नेतृत्व और इनोवेशन की ताकत को न केवल प्रदेश बल्कि पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब युवा स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ता है और आत्मनिर्भर बनता है, तो बेरोजगारी की दर अपने आप कम हो जाती है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से अधिक थी, जो अब घटकर 2.24 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

संपादकीय

बांग्लादेश में राजनैतिक बदलाव

भारत से पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा राजनैतिक बदलाव आया है। देश आखिरकार एक स्थिर सरकार हासिल करने की तरफ बढ़ा है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई थी, और उन्हें भारत में राजनैतिक शरण लेकर अपनी प्राणरक्षा करनी पड़ी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चली और इस दौरान न केवल अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए अविचारित हिंसा की गई, बल्कि भारत के खिलाफ तल्खी बढ़ाने वाले कई बयान अहम पदों पर बैठे नेताओं ने दिए। बांग्लादेश ने उस पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाई है, जिसके अत्याचारों के कारण उसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से अलग करवाया था। बहरहाल, युनूस सरकार पर लगातार चुनाव करवाने का दबाव बना, आखिरकार 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में अवामी लीग को हिस्सा लेने नहीं दिया गया। शेख हसीना ने इन चुनावों को रद्द करने की मांग की है, लेकिन अब यह तय है कि तारिक रहमान देश की कमान संभालने जा रहे हैं। पिछले 35 सालों में शेख हसीना और खालिदा जिया ही बांग्लादेश का नेतृत्व करती रहीं, लेकिन अब बेगमों का राज बांग्लादेश में इतिहास बन गया है और दिवंगत खालिदा जिया के बेटे देश संभालने जा रहे हैं। 17 फरवरी को तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसमें उन्होंने सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जाहिर है सार्क में पाकिस्तान भी है और शाहबाज शरीफ संभवतरू बांग्लादेश पहुंचेंगे ही। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को तारिक रहमान से फोन पर बात की और सोशल मीडिया पर बधाई भी दी। तारिक रहमान ने भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा जताई है। लेकिन क्या मात्र इच्छा जताने से दोनों देशों के बीच उलझे हुए तार सुलझेंगे, ये देखना होगा। तारिक रहमान ने अमेरिका फर्स्ट के नारे की तरह श्बांग्लादेश फर्स्टश का नारा दिया है। जो राष्ट्रवाद के नए फैशन की तरह बन चुका है। बेशक हर राजनेता, हर राष्ट्रप्रमुख अपने ही देश को सर्वोपरि रखता है, लेकिन उसे फलाना फर्स्ट या ढिकाना फर्स्ट के नारे के तहत व्याख्यायित करना जुबानी प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है। तारिक रहमान ने कहा है कि भारत, चीन और पाकिस्तान से बराबर दूरी रखना चाहते हैं। उन्होंने पहले कहा था, श्न दिल्ली, न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले।श अब जीत के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक रहमान ने कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश और उसके लोगों के हितों पर आधारित होगी। कोई देश–केंद्रित नीति नहीं होगी। उन्होंने कहा, श्चीन विकास के मामले में दोस्त है, लेकिन अगर कुछ बांग्लादेश के हित में नहीं होगा तो हम उसे नहीं मानेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखेंगे कि क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।श वहीं शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अवामी लीग समर्थकों पर केस और परेशानी के बारे में कहा कि कानून का राज चलेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से एकता की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण में सबकी जरूरत है। चुनाव के बाद कोई बदला या हिंसा नहीं होगी। उन्होंने अपनी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने को कहा और विजय जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया। बता दें कि बीएनपी ने 300 में से करीब 209 सीटें जीतीं। वहीं जमात–ए–इस्लामी ने 68 सीटें जीतीं हैं, जो भारत के लिए चिंता का सबब है। तारिक रहमान ने तो भारत के साथ अच्छे संबंधों को रखने की इच्छा जताई है, लेकिन शेख हसीना का प्रत्यर्पण और जमात के प्रभाव में उठती भारत–विरोधी आवाजों को शांत करने के मुद्दे पर वे क्या करते हैं, उसी के आधार पर पता चलेगा कि आगे जाकर भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रहेंगे। जमात–ए–इस्लामी और उसके 11 सहयोगियों ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से लगे बांग्लादेशी जिलों में स्थित हैं। जमात की चुनावी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने पश्चिम बंगाल के छह जिलों जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से लगी सीमा के साथ–साथ असम के सिलचर से लगे क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित कर लिया है। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि यह स्थिति भारत के सीमा सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकती है। सीमा के वे हिस्से जहां कंटीले तार नहीं लगे हैं, वे लंबे समय से मानव तस्करी और तस्करी के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। इस फैसले के बाद भारत को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ढाका के राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है कि सरहदी क्षेत्रों में जमात की जीत की एक बड़ी वजह ये है कि उन क्षेत्रों में बंटवारे के बाद भारत से आने वाले मुसलमान हैं। उनके वंशज जमात को वोट कर रहे हैं और उनकी आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत में जल्द ही असम और प.बंगाल में चुनाव हैं, जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश भाजपा कर रही है। पड़ोसी जिलों में जमात की मौजूदगी इस ध्रुवीकरण को न केवल बढ़ाएगी, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा करेगी। अब नरेन्द्र मोदी पर निर्भर करता है कि वे भाजपा का चुनावी हित पहले रखते हैं या देश की आंतरिक सुरक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी।

राशिफल

मेष :– विचारों की अस्थिरता आपको उलझनपूर्ण परिस्थिति में डालेगी। नौकरी–व्यवसाय के क्षेत्र में स्पर्धायुक्त वातावरण रहेगा। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। प्रवास की संभावना है।

वृषभ :– मन की दुविधा ठोस निर्णय पर आने से रोकेगी जिससे हाथ आए अवसर आप खो देंगे। झक्वी व्यवहार के कारण संघर्ष में उतरने की संभावना है। नए कार्य के लिए दिन अच्छा नहीं है।

मिथुन :– आज का दिन लाभदायक साबित होने की आशा रख सकते हैं। सुबह से ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होगा। आर्थिक लाभ मिलने के साथ–साथ कहीं से गिफ्ट प्राप्त हो सकता है।

कर्क :– शरीर और मन में बेचौनी और अस्वस्थता का अनुभव होगा। मन की संदिग्धता और दुविधा आपकी निर्णयशक्ति को कसौटी के शिखर पर चढ़ाएंगे। वाद–विवाद से दूर रहें।

सिंह :– आज के दिन आपको विविध लाभ मिलने की संभावना है। ऐसे समय में मन का ढीलापन आपको लाभ से वंचित न कर दे, इसका ख्याल रखें। पदोन्नति और आय वृद्धि का योग है।

कन्या :– नए कार्य शुरू करने के लिए निर्मित योजनाओं को अमल में लाने का आज उत्तम समय है। व्यापार में लाभ होगा। बकाया वसूली के पैसे वापस मिलेंगे। पिता की तरफ से लाभ होगा।

तुला :– लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक स्थान की मुलाकात होगी। विदेश यात्रा के लिए अनुकूलता रहेगी। फिर भी आपको संतान और स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। धन का खर्च होगा।

वृश्चिक :– आज का दिन सावधानीपूर्वक बिताएं। नए कार्य शुरू न करें। क्रोध, आवेश और अनैतिक आचरण आपको कठिनाई में डाल सकते हैं। दुर्घटना से बचें।

धनु :– बौद्धिक, तार्किक, विचार–विनिमय और लेखन कार्य के लिए शुभ दिन है। भागीदारी में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ के सम्बंधों में अधिक घनिष्ठता रहेगी। मान–सम्मान मिलेगा।

मकर :– आज से आपके व्यापार–धंधे का विकास होगा। आर्थिक रूप से लाभदायक दिन होने से पैसे की लेन–देन में सरलता रहेगी। परिवार में सुख– शांति का माहौल रहेगा।

कुंभ :– आज आप संतान और अपने स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंतित रहेंगे। अपच, पेट–दर्द से परेशान होंगे। विचारों में तेजी से परिवर्तन मानसिक स्थिरता में खलल पहुंचाएगा।

मीन :– शारीरिक– मानसिक भय रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ वाद–विवाद होगा। माताजी का स्वास्थ्य खराब होगा। अनचाही घटनाओं से आपके उत्साह में कमी आएगी। अनिद्रा से परेशान रहेंगे।

दाढ़ी पर नहीं, सोच पर बहस ज़रूरी

फैशन, पहचान और भ्रम : आज के युवाओं के सामने असली चुनौती

–डॉ. सत्यवान सौरभ

हर दौर की अपनी पहचान होती है। यह पहचान केवल कपड़ों, हेयर–स्टाइल या चेहरे पर उगे बालों से नहीं बनती, बल्कि उस सोच से बनती है जो व्यक्ति और समाजकृ दोनों को दिशा देती है। आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे कैसे दिखते हैं यह कम, और क्या सोचते हैं तथा किसका अनुकरण करते हैंकृयह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बाहरी आकर्षण, सोशल मीडिया की चमक और तात्कालिक लोकप्रियता ने पहचान की परिभाषा को सतही बना दिया है। बीते कुछ वर्षों में दाढ़ी को लेकर एक तीखी बहस उभरी है। कुछ लोग इसे आधुनिक फैशन का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे सांस्कृतिक भ्रम और अंधानुकरण का उदाहरण। यह बहस तब और जटिल हो जाती है जब इसे धर्म, राजनीति या साज़िश से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर, शोर से दूर रहकर, विवेकपूर्ण और तथ्यपरक दृष्टि से इस विषय को देखें। क्योंकि जब मुद्दे विचार के बजाय पहचान की लड़ाई बन जाते हैं, तब समाधान नहीं, विभाजन पैदा होता है। इतिहास गवाह है कि दाढ़ी और क्लीन शेवकृ दोनों ही भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। वैदिक काल के ऋषि–मुनि जटाधारी थे, तो राजदरबारों में सुसज्जित, साफ़–सुथरे व्यक्तित्व भी दिखाई देते थे। मध्यकाल हो या आधुनिक कालकृहर युग में दोनों प्रकार के रूप साथ–साथ मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित नेहरूकृसभी का रूप अलग था, पर उद्देश्य एक। स्पष्ट है कि दाढ़ी कोई नई या बाहरी चीज़ नहीं है, और न ही क्लीन शेव कोई विदेशी अवधारणा। दोनों ही समय, परिस्थिति और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार बदलते रहे हैं। आज दाढ़ी का चलन केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक फैशन का हिस्सा बन चुका है। हॉलीवुड, यूरोपीय फैशन, खेल जगत, संगीत उद्योग और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्सकृहर जगह दाढ़ी अलग–अलग शैलियों में दिखाई देती है। सोशल मीडिया ने इन रुझानों को और तेज़ कर दिया है। एक तस्वीर, एक वीडियो या एक रील के ज़रिये ट्रेंड पल भर में दुनिया भर में फैल जाते हैं। ऐसे में यह मान लेना कि कोई एक उद्योग, समूह या विचारधारा ही किसी फैशन को "फैला" रही है, वास्तविकता का सरलीकरण होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अंधानुकरण एक गंभीर समस्या बन चुका है। जब युवा किसी भी ट्रेंड को बिना सोचे–समझे केवल इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह लोकप्रिय है या "कूल" माना जा रहा है, तब उनका व्यक्तित्व उधार का हो जाता है। फैशन तब समस्या बनता है जब वह सोच पर हावी हो जाए और पहचान को केवल बाहरी प्रतीकों तक सीमित कर दे। सवाल दाढ़ी रखने या न रखने का नहीं है; सवाल यह है कि क्या हम अपने चुनाव के कारण जानते हैं, या सिर्फ़ भीड़ के साथ चल रहे हैं? इस संदर्भ में सिनेमा और डिजिटल मीडिया की भूमिका पर चर्चा ज़रूरी है। मनोरंजन उद्योग न केवल कहानियाँ सुनाता है, बल्कि जीवन–शैली के मानक भी गढ़ता है। बार–बार एक ही तरह के "लुक", "स्टाइल" और "हीरोइज़्म" को आदर्श बनाकर प्रस्तुत करने से युवाओं के सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं। इससे विविधता कम होती है और एकरूपता बढ़ती है। जिम्मेदार मीडिया वही है जो समाज की बहुलता को दिखाएकृजहाँ सादगी भी आकर्षक हो, और अलग–अलग व्यक्तित्व भी स्वीकार्य हों। लेकिन दर्शक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दिखावे और मूल्य में अंतर करना सीखें। ईश्वर, संस्कृति और सौंदर्य की चर्चा में भी संतुलन आवश्यक है। हमारी परंपराएँ अत्यंत विविध रही हैं। कहीं जटाधारी तपस्वी हैं, तो कहीं सुसज्जित देव–प्रतिमाएँ; कहीं वैराग्य है, तो कहीं श्रृंगार। सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी रूप

नहीं, बल्कि आचरण, करुणा, संयम और विवेक है। यदि हम सौंदर्य को केवल चेहरे, दाढ़ी या फैशन तक सीमित कर दें, तो हम अपनी ही सांस्कृतिक गहराई को कम कर देते हैं। आज के युवाओं के सामने असली खतरा किसी एक फैशन से नहीं, बल्कि आत्मबोध की कमी से है। जब युवा अपने इतिहास, मूल्यों और सांस्कृतिक बहुलता को समझते हैं, तब वे किसी भी ट्रेंड को अपनाएँकृया न अपनाएँकृवह उनका सजग और स्वतंत्र निर्णय होता है। लेकिन जब पहचान केवल बाहरी प्रतीकों पर टिक जाती है, तब भ्रम पैदा होता है और व्यक्ति आसानी से प्रभावित हो जाता है। समाधान डर, आरोप या साज़िश की भाषा में नहीं है। समाधान शिक्षा, संवाद और आत्मविश्वास में है। युवाओं को यह समझाना ज़रूरी है कि फैशन क्षणिक होता है, लेकिन चरित्र स्थायी। आज जो ट्रेंड है, कल बदल जाएगा; पर जो मूल्य आप अपनाते हैं, वही जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए चयन सोच–समझकर होना चाहिएकृन दबाव में, न डर में, और न ही अंधानुकरण में। समाज को विभाजन की भाषा से भी सावधान रहना चाहिए। जब हम किसी चलन को डर या साज़िश के चश्मे से देखते हैं, तो संवाद बंद हो जाता है और ध्रुवीकरण बढ़ता है। इसके विपरीत, जब हम प्रश्न पूछते हैंकृ"क्यों?", "कैसे?" और "किस हद तक?"कृ तब समझ विकसित होती है। स्वस्थ समाज वही है जो असहमति को जगह देता है, लेकिन सम्मान और तथ्य के साथ। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम युवाओं को आलोचनात्मक सोच सिखाएँकृताकि वे हर ट्रेंड को आँख बंद करके न अपनाएँ। उन्हें अपने शरीर, समय और पहचान पर अधिकार का बोध हो। फैशन अपनाना गलत नहीं; गलत है फैशन के पीछे खुद को खो देना। व्यक्तित्व की असली सुंदरता बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और विवेक में होती है। अंततः, यह बहस दाढ़ी की नहीं, दिशा की है। हम अपनी पहचान किस पर बना रहे हैंकृदिखावे पर या विचार पर? यदि हम युवाओं को शिक्षा, अवसर और आत्मसम्मान देंगे, तो वे किसी भी फैशन में सुरक्षित रहेंगेकृक्योंकि उनकी जड़ें मज़बूत होंगी। समाज का भविष्य बाहरी रूपों से नहीं, सोच की मजबूती से तय होता है। और वही सोच हमें यह सिखाती है कि ट्रेंड आते–जाते रहते हैं, लेकिन मूल्य वही होते हैं जो समय की कसौटी पर टिकते हैं।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

कोचिंग संस्कृति और बच्चों की मौतें : सफलता के नाम पर असफल समाज

–डॉ० प्रियंका सौरभ

कोटा में एक और छात्रा की आत्महत्याकृयह कोई साधारण खबर नहीं है और न ही किसी एक परिवार की निजी त्रासदी भर। यह उस शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक मानसिकता और तथाकथित "सफलता मॉडल" पर गहरा प्रश्नचिह्न है, जिसे हमने पिछले दो दशकों में बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है। आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति का सुसाइड नोट केवल व्यक्तिगत पीड़ा का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि वह एक आरोपपत्र की तरह हमारे पूरे समाज के सामने खड़ा होता हैकृमाता–पिता, कोचिंग संस्थान, स्कूल और नीति–निर्माता सभी इसके दायरे में आते हैं।

कृति ने अपने सुसाइड नोट में भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से अपील की थी कि अगर वे सच में चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे, तो कोचिंग संस्थानों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान छात्रों को भीतर से खोखला कर देते हैं। यह कथन किसी क्षणिक आवेग का परिणाम नहीं था, बल्कि उस लंबे मानसिक उत्पीड़न की अभिव्यक्ति थी, जिसे आज लाखों छात्र रोज़ झेल रहे हैं। असली सवाल यह नहीं है कि कृति ने ऐसा क्यों लिखा, बल्कि यह है कि क्या वह

ग़लत थी। आज भारत में कोचिंग शिक्षा का सहायक माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि एक विशाल और मुनाफ़े पर आधारित उद्योग बन चुकी है। कोटा, सीकर, हैदराबाद, दिल्ली और पटना जैसे शहर "एजुकेशन हब" कहलाते हैं, जहाँ हर साल लाखों किशोर अपने माता–पिता के सपनों का बोझ उठाए पहुँचते हैं। इन सपनों के केंद्र में कुछ सीमित शब्द होते हैंकृआईआईटी, एम्स, नीट, रैंक और सेलेक्शन। कोचिंग संस्थान बच्चों को यह यक़ीन दिलाते हैं कि यदि वे चयनित नहीं हुए, तो वे असफल हैं। सफलता की यह परिभाषा इतनी संकीर्ण है कि उसमें औसत छात्र के लिए कोई जगह नहीं बचती, और असफलता से उबरने की कोई मानवीय प्रक्रिया भी नहीं होती। कृति का यह कथन कि "90+ अंक लाने वाली लड़की भी आत्महत्या कर सकती है" हमारे उस भ्रम को तोड़ता है, जिसमें हम यह मान लेते हैं कि मानसिक संकट केवल कमजोर या असफल छात्रों तक सीमित है। यह सोच न सिर्फ़ ग़लत है, बल्कि ख़तरनाक भी है। आज का दबाव केवल परीक्षा पास करने या अच्छे अंक लाने का नहीं रह गया है, बल्कि माता–पिता, शिक्षकों और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का बन गया है। हर बच्चा अपने भीतर एक काल्पनिक 'परफेक्ट स्टूडेंट' की छवि ढो रहा है, जिससे वह लगातार हारता चला जाता है। ऊँचे अंक और बेहतर प्रदर्शन भी अब मानसिक शांति की गारंटी नहीं रहे, क्योंकि समस्या पढ़ाई की नहीं, बल्कि उस माहौल की है जिसमें पढ़ाई कराई जा रही है। कृति द्वारा अपनी माँ के लिए लिखी गई पंक्तियाँ इस पूरे संकट की जड़ को उजागर करती हैं। वह बताती है कि उसे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसकी वास्तविक रुचि अंग्रेज़ी साहित्य और इतिहास में थी। यह कहानी किसी एक घर तक सीमित नहीं है। यह देश के हज़ारों, बल्कि लाखों घरों की सच्चाई है, जहाँ बच्चे की रुचि से ज़्यादा समाज की अपेक्षा मायने रखती है। माता–पिता अक्सर यह भूल जाते हैं कि बच्चा उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। सामाजिक तुलनाकृकि फलाँ का बेटा डॉक्टर बन गया या फलाँ की बेटी आईआईटी में पहुँच गईकृहमें इतना अंधा कर देती है कि हम बच्चों की इच्छाओं, क्षमताओं और सीमाओं को अनदेखा कर देते हैं। कृति ने अपनी छोटी बहन को लेकर जो चेतावनी दी, वह इस सुसाइड नोट को और भी मार्मिक बना देती है। वह चाहती है कि उसकी बहन को वही पढ़ने दिया जाए, जो वह पढ़ना चाहती है, और वही बनने दिया जाए, जो वह बनना चाहती है। यह विडंबना है कि मरते समय भी वह किसी और की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। यह चेतावनी केवल एक माँ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है, जो बच्चों को सुनने के बजाय उन पर अपने सपने थोपता है। आज के स्कूल और कोचिंग संस्थान बच्चों को गणित के सूत्र, रसायन के समीकरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीतियाँ तो सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन के सबसे ज़रूरी पाठ सिखाने में पूरी तरह असफल हो रहे हैं। वे बच्चों को यह नहीं सिखा पा रहे कि असफलता से कैसे निपटना है, मानसिक तनाव को कैसे समझना है और मदद माँगना कमजोरी नहीं है। प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा के बजाय भय का औज़ार बना दिया गया है। रैंक लिस्ट, मॉक टेस्ट और लगातार तुलना बच्चों के मन में स्थायी हीनभावना भर देती है, जिससे वे खुद को केवल अंकों और चयन के चश्मे से देखने लगते हैं। हर ऐसी मौत के बाद सरकार की ओर से औपचारिक बयान आते हैं, जाँच के आदेश दिए जाते हैं और कुछ दिनों तक बहस चलती है। इसके बाद सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। न कोचिंग संस्थानों के कामकाज पर सख़्त निगरानी होती है, न उनके घंटे सीमित किए जाते हैं, न मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाता है। यदि सरकार सच में गंभीर है, तो कोचिंग उद्योग के लिए सख़्त नियमन, छात्रों के लिए सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सहायता और स्कूल स्तर पर करियर की विविध संभावनाओं को स्वीकार करने की ठोस नीति बनानी होगी। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम सफलता को किस रूप में परिभाषित करते हैं। क्या एक अच्छा इंसान बनना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और अपनी रुचि के क्षेत्र में संतुष्ट जीवन जीना सफलता नहीं है? यदि नहीं, तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो चयनित तो होगी, लेकिन भीतर से टूटी हुई और असंतुष्ट होगी। कृति की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम अपने बच्चों को ज़िंदा रहते हुए ही तो नहीं मार रहेकृउनकी इच्छाओं को, उनके सपनों को और उनकी स्वतंत्रता को। कृति का सुसाइड नोट केवल एक छात्रा की अंतिम अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। अगर अब भी हमने नहीं सुना, नहीं समझा और नहीं बदले, तो ऐसी घटनाएँ रुकने वाली नहीं हैं। सवाल यह नहीं है कि अगला बच्चा कौन होगा। असली सवाल यह है कि क्या हम अगले बच्चे को बचा पाएँगे।

नारी ही परिवार की खुशी, राष्ट्र का गौरव और सुख की धुरी है

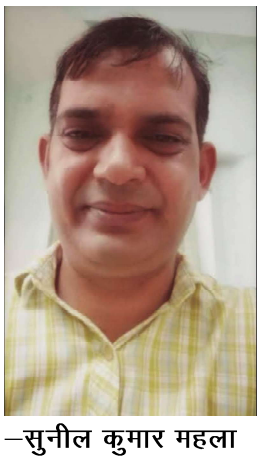

–सुनील कुमार महला

स्त्री की गरिमा और उसका सम्मान भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा रहे हैं। हमारे यहां नारी को शक्ति, करुणा और सृजन का प्रतीक माना गया है तथा शास्त्रों में कहा गया है–श्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।श यहां पाठकों को बताता चलूं कि यह प्रसिद्ध संस्कृत वचन श्मनुस्मृतिश से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जहां नारी का सम्मान और आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है। वास्तव में, यह कथन भारतीय संस्कृति में स्त्री के उच्च और पूजनीय स्थान को दर्शाता है। नारी को शक्ति, करुणा, त्याग और सृजन की प्रतीक माना गया है।सच तो यह है कि परिवार और समाज की असली आधारशिला नारी ही होती है और जिस समाज में महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा मिलती है, वह समाज और देश प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत, जहां नारी का अपमान होता है, वहां अशांति और पतन का वातावरण बनता है। इसलिए नारी सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक आवश्यकता भी है।इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और अहिल्याबाई होल्कर जैसी महान महिलाओं ने साहस, नेतृत्व और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। परिवार और समाज के निर्माण में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है; वह मां, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में जीवन को संवेदना, संतुलन और संस्कार प्रदान करती है। आज के आधुनिक युग में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्त्री का सम्मान केवल परंपरा या शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार, सोच और सामाजिक व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में उन्नत और सभ्य बन सकेगा। बहरहाल, स्त्रियों की गरिमा व सम्मान के क्रम में हाल ही में जैस्मीन सैंडलस ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा और साहसी कदम उठाया। जब कुछ लोग वहां मौजूद लड़कियों और महिलाओं को परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने गाना बीच में ही रोक दिया। बहरहाल,यहां पाठकों को बताता चलूं कि जैस्मीन सैंडलस एक प्रसिद्ध भारतीय–अमेरिकी पंजाबी गायिका और गीतकार हैं, जिन्होंने अपने अलग अंदाज़ और दमदार आवाज़ से संगीत जगत में खास पहचान बनाई है। उनका जन्म 4 सितंबर 1985 को पंजाब के जालंधर में हुआ और बाद में वह अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में पली–बढ़ीं। उन्होंने 2007 में अपने करियर की शुरुआत की और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में तेजी से लोकप्रिय हुईं। बॉलीवुड में उन्हें बड़ी पहचान फिल्म श्किकश के गीत श्यार ना मिलेश से मिली। उनके गानों में पॉप, आर एंड बी और पंजाबी फोक का मिश्रण देखने को मिलता है। जैस्मीन न सिर्फ गायिका हैं बल्कि अपने कई गीत स्वयं लिखती भी हैं, और अपनी बेबाक शैली व ऊर्जावान स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं।जैस्मीन सैंडलस ने संगीत कार्यक्रम के दौरान यह बात साफतौर पर कहीं कि जब तक महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, वह मंच पर नहीं गाएंगी। वास्तव में,यह घटना बताती है कि आज भी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। घर से बाहर निकलते ही उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। दुख की बात यह है कि ऐसे मामलों में कई लोग सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं।आज आए दिन मीडिया की सुर्खियों में यह खबरें हमें पढ़ने को मिलतीं रहतीं हैं कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को आज अभद्र टिप्पणियों, घूरने, छेड़छाड़ और उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस, ट्रेन, बाजार, दफ्तर या यहां तक कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी वे असुरक्षा की भावना से घिरी रहती हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि घर से बाहर कदम रखते ही उन्हें अपने कपड़ों, समय और रास्तों तक के बारे में सोच–समझकर निर्णय लेना पड़ता है। वास्तव में,यह स्थिति केवल कानून व्यवस्था की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच की समस्या भी है। जब तक महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और संवेदनशीलता की भावना समाज में मजबूत नहीं होगी, तब तक केवल सख्त कानून भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाएंगे। परिवार, विद्यालय और समाज सभी को मिलकर ऐसी मानसिकता विकसित करनी होगी, जिसमें महिला को स्वतंत्र और सुरक्षित नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाए। वास्तव में, सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना सरकार, प्रशासन और हम सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। सीसीटीवी, हेल्पलाइन, त्वरित कार्रवाई जैसे उपाय जरूरी हैं, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार। जब महिलाएं बिना भय के स्वतंत्र रूप से बाहर निकल सकेंगी, तभी समाज वास्तव में प्रगतिशील कहलाएगा। हाल फिलहाल, जैस्मीन सैंडलस का यह कदम सिर्फ एक कार्यक्रम रोकना नहीं था, बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना था। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी हालत में महिलाओं के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। कहना ग़लत नहीं होगा कि उनका यह साहस पूरे समाज के लिए एक सीख है। अंत में यही कहूंगा कि, जैसा कि हमारी संस्कृति में कहा गया है कि –शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।न शोचन्ति च यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा।।श तात्पर्य यह है कि जहाँ परिवार की स्त्रियाँ दुखी रहती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है, और जहाँ वे प्रसन्न रहती हैं, वह परिवार सदैव उन्नति करता है। वास्तव में नारी ही परिवार की खुशी, राष्ट्र का गौरव और सुख की धुरी है, इसलिए उन्हें सदैव सम्मान मिलना चाहिए।

कांग्रेस मुक्त हुई विधान परिषद, सपा ऐसा कार्य न करे कि विधानभवन मुक्त होना पड़े: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान परिषद में कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेताओं को धोया

रामराज्य की आधारभूमि के रूप में नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेशः सीएम योगी

बोले- समाज को लड़ाने के साथ ही संवैधानिक मूल्य पर भी प्रहार करने से नहीं चूक रहे सपाई, एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े लोगों के साथ मारपीट कर रहे सपा कार्यकर्ता

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान परिषद में कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेताओं को खूब धोया। सीएम ने विधान परिषद की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के सदस्यों से कहा कि कांग्रेस से सबक ले लीजिए। कांग्रेस विधान परिषद विहीन हो गई है। यदि सपा को भी विधानसभा व परिषद विहीन होना है तो अनर्गल प्रलाप और महापुरुषों का अपमान करे। अन्यथा ऐसा आचरण न करें, जो समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करता है। सीएम ने विपक्षी दलों के सदस्यों से अनुरोध किया कि यूपी की नई पहचान को संकट में मत डालिए। प्रदेश के विकास की यात्रा के साथ बढ़ने के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो प्रदेश की जनता आपको सम्मानित करेगी।

रामराज्य की आधारभूमि के रूप में नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सभी सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश और देश में जब टीमवर्क से काम होता है, तब परिणाम आता है। आज हर तबके (गांव, गरीब, युवा, महिला, किसान, हस्तशिल्पी) के मन में विश्वास है और यह विश्वास हर सेक्टर में दिख रहा है। आज यूपी में कानून का राज, अपराधी भयभीत, गरीब को सम्मान, किसान खुशहाल, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर,

हर गांव में बिजली और हर हृदय में गर्व है। यूपी फिर से रामराज्य की आधारभूमि के रूप में नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है।

सपा ने न कुछ अच्छा किया और न ही अच्छा बोल पाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने जनकल्याण, रोजगार सृजन, निवेश विस्तार के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से सशक्त, सुरक्षित व समृद्ध प्रदेश के रूप में अपनी नई पहचान को बनाया है। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 2029–30 में यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के रूप में स्थापित करना है। हमने बजट भी उस दिशा में ही प्रस्तुत किया है।

सीएम योगी ने कहा कि बजट के बारे में समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं बोल पाई, क्योंकि अच्छा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्होंने न अच्छा किया और न ही अच्छा बोलेंगे। हमारी सरकार ने डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए पूरी मजबूती के साथ प्रदेश में प्रधानमंत्री के विजन को बढ़ाया है। सीएम ने कहाकि बहुत सारे सेक्टर हैं, जिसमें यह लोग गुमराह कर रहे हैं।

समाज को लड़ाने के साथ ही संवैधानिक मूल्य पर भी प्रहार करने से नहीं चूक रहे सपाई

सीएम ने संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विपक्षी दलों के भाव की निंदा की। बोले कि समाजवादी पार्टी के नेता बयानों से जातीय संघर्षों को बढ़ावा देते हैं। समाज को आपस में लड़ाने, आस्था का अपमान, गुंडागर्दी व अराजकता को बढ़ाने के साथ संवैधानिक मूल्य पर भी प्रहार करने में नहीं चूक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में एसआईआर की कार्यवाही चल रही है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती है। आयोग की गाइडलाइन पर तंत्र उसका अनुपालन करता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की कार्यवाही का जिक्र करते हुए सदन में मुख्यमंत्री ने बताया कि 2.88 करोड़ से अधिक लोग अनुपस्थित/मृत या शिफ्टिंग हैं। समाजवादी पार्टी इन्हें जबर्दस्ती वोट बनाकर फर्जी पोलिंग करती थी। सपा चिल्ला रही है कि फॉर्म–7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। सीएम ने आयोग द्वारा बनाई गई फॉर्म–6, फॉर्म–7 व फॉर्म–8 की व्यवस्था की उपयोगिता बताई।

एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े लोगों के साथ मारपीट कर रहे सपा कार्यकर्ता

सीएम ने कहा कि सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ और अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर रहे हैं, यह शोभा नहीं देता। यह संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना, मजाक, अपमान है। अगर हम संविधान की शपथ लेते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान दें। संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा अपने अनुरूप तय करें, यह अस्वीकार्य है।

यूपी में शिक्षा व स्कूलों की स्थिति हुई बेहतर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर अब शिक्षा व स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है। बेसिक शिक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प, श्रमिकों व निराश्रित बच्चों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अटल आवासीय विद्यालय समेत यूपी ने बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए हैं। हर जनपद में दो–दो सीएम कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि इसकी नेटवर्किंग को न्याय पंचायत स्तर तक फैलाकर प्री–प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एक कैंपस में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो। एडेड–गवर्नमेंट कॉलेज और प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक शिक्षा को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई है। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 150 आईटीआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (एआई, ड्रोन, रोबोटिक) समेत इन सभी में प्रदेश ने कार्य प्रारंभ किया है। राजकीय व निजी क्षेत्र में भी लगभग 75 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, जो यह उच्च शिक्षा के बेहतरीन केंद्र बनकर उभरे हैं।

तेज रफ्तार डाला पलटा, बाइक सवार दंपती-बच्ची घायल

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार टेंपो डाला अनियंत्रित होकर एक बाइक पर पलट गया। इस हादसे में बाइक सवार डीसीएम चालक मोहर्रम अली (45), उनकी पत्नी किस्मतुन्निशा (40) और 10 साल की बेटी सुमायरा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल डाला उठाकर उसके नीचे दबे तीनों घायलों को बाहर निकाला। 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन पहुंचने में देरी होने पर लतीफ नगर के प्रधान प्रतिनिधि तरुण शुक्ला ने अपनी कार से तीनों को कटी बगिया स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। उनका इलाज जारी है। मोहर्रम अली उन्नाव जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित समदपुर जसमड़ा के रहने वाले हैं, वह अपनी पत्नी किस्मतुन्निशा और बेटी सुमायरा के साथ रायबरेली स्थित रिश्तेदारी से बंथरा के बनी मोहान रोड होते

हुए बाइक से वापस घर जा रहे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने डाला चालक प्रमोद साहू को पकड़ लिया। प्रमोद साहू बंथरा के रहीमनगर पड़ियाना का निवासी है। लोगों ने डाला और उसके चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह घटना डाला चालक की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि वह अक्सर तेज रफ्तार में वाहन चलाता है। बंथरा पुलिस ने डाला और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

चोरी की एयर गन समेत लाखों का सामान बरामद

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के पीजीआई इलाके में बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की एक एयर गन और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 42,362 रुपये मूल्य के पीली धातु के जेवर बरामद किए हैं। इनमें अंगूठी, चेन, पेंडेंट, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स,झाले, मांग टीका, हाथ फूल, गले का हार और चूड़ियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सफेद धातु के जेवर जैसे चेन, कान के टॉप्स,झाले, गले का हार, पायल,पाजेब, अंगूठी, चार हाथ घड़ियां और दो मोतियों की माला भी मिली है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सोनू सिंह, शक्तिमान सिंह और सोनू कुमार साह उर्फ सोनू पहाड़ी के रूप में हुई है, जो बिहार के निवासी हैं। चौथा आरोपी बृजेश निषाद फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र के किशनपुर रम सगरा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, आरोपी सोनू सिंह पर पहले से नौ मुकदमे दर्ज हैं।

पालि साहित्य और बौद्ध दर्शन पर होगा मंथन, बीएचयू में जुटेंगे 8 देशों के विद्वान

संवाददाता

लखनऊ। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग की ओर से 17 से 19 फरवरी तक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और तोयो विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में होगा। इसका उद्देश्य पालि साहित्य, बौद्ध दर्शन, त्रिपिटक अध्ययन, अलग–अलग बौद्ध परंपराओं की तुलना, बौद्ध संस्कृति और विरासत, पांडुलिपि विज्ञान और आज के समय में बौद्ध विचारों की अहमियत जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा करना है। तीन दिनों में 80 चुने हुए शोध–पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में म्यांमार, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, जापान, थाईलैंड और वियतनाम समेत कई देशों के विद्वान, शोधकर्ता, प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। तकनीकी सत्रों में पालि त्रिपिटक, अट्ठकथा परंपरा, बौद्ध तर्कशास्त्र, थेरवाद और महायान दर्शन, तुलनात्मक बौद्ध अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संवाद जैसे विषयों पर शोध–पत्र पढ़े जाएंगे।17 फरवरी को होने वाले उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रो. सिद्धार्थ सिंह कुलपति, नव नालंदा महाविहार होंगे। सत्र की अध्यक्षता प्रो. रवींद्र पंथ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कनफेडरेशन करेंगे।19 फरवरी को ल समापन सत्र की अध्यक्षता प्रो. उमा शंकर व्यास, पूर्व निदेशक, नव नालंदा महाविहार करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. राजेश रंजन, कुलपति, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान शामिल होंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सम्मेलन भारत और एशिया के दूसरे देशों के बीच बौद्ध शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शोध के रिश्तों को और मजबूत करेगा। इससे भारत को दुनिया में बौद्ध ज्ञान के एक बड़े केंद्र के रूप में पहचान मिलेगी। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग बौद्ध शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। पालि भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में मानी जाती है। इसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, जिसका प्रमाण सम्राट सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से मिलता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पालि भाषा में ही दिए थे और उस समय यह आम लोगों की भाषा थी। केंद्र की भारत सरकार ने पालि भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे इस भाषा के संरक्षण और अध्ययन को नई मजबूती मिली है।

विधानसभा में गूंजा निजी अस्पतालों की मनमानी और आशा बहुओं का मुद्दा

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को निजी अस्पतालों की कथित मनमानी का मुद्दा जोर–शोर से उठा। समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य अतुल प्रधान ने सरकार से सवाल किया कि निजी अस्पतालों पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और मरीजों से मनमाने शुल्क वसूलने की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है। इस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्य अब भी

अपना चश्मा नहीं बदल पा रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार के नजरिए से ही वर्तमान व्यवस्था को देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों की अनियमितताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और किसी को भी मनमानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाठक ने बिना नाम लिए यह भी कहा कि कुछ लोग अस्पतालों से उगाही के चक्कर में लगे हुए हैं और सरकार ऐसे तत्वों पर भी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दौरान सदन में आशा बहुओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग भी उठी। समाजवादी पार्टी के विधायक आर के बर्मा ने आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और उनके वेतन में वृद्धि की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली आशा बहुएं सीमित मानदेय में व्यापक जिम्मेदारियां निभा रही हैं, ऐसे में उन्हें उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

डीएम कार्यालय पर इंडो-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में सोमवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।

भारत–अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में कृषि और दुग्ध उत्पादों को शामिल किए जाने की आशंका को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद गुप्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कृषि हितों की रक्षा की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष (पूर्वी उत्तर प्रदेश) प्रताप बहादुर ने कहा कि यदि व्यापार समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर को शामिल किया गया तो इसका सीधा असर देश के छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 87 प्रतिशत किसान सीमांत श्रेणी में आते हैं। उनकी आजीविका खेती व पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में विदेशी उत्पादों की एंट्री से उनकी आय प्रभावित हो सकती है। ज्ञापन में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की कृषि सचिव ब्रूक रोलिंस के हालिया बयानों से यह संकेत मिलता है कि प्रस्तावित समझौते से अमेरिकी किसानों को लाभ पहुंच सकता है। संगठन ने आशंका जताई कि यदि अमेरिकी दुग्ध उत्पाद या मिल्क पाउडर भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर आया तो स्थानीय डेयरी व्यवसाय संकट में पड़ सकता है। किसान नेताओं ने कहा कि देश के कई हिस्सों में दूध पहले से ही कम कीमत पर बिक रहा है। ऐसे में विदेशी उत्पादों की आमद से बाजार दर और गिर सकती है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया। संगठन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि प्रस्तावित इंडो–अमेरिका व्यापार समझौते में कृषि और पशुपालन क्षेत्र को शामिल न किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी हुई तो देशभर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा।

योगी सरकार की 'उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026'

25 वर्ष से ज्यादा पुराने प्रोजेक्ट्स को मिलेगी नई जिंदगी

नियोजन मानकों में व्यावहारिक लचीलापन, बोर्ड अनुमोदन से तेज होगा अमल

संवाददाता

लखनऊ। बढ़ते शहरीकरण और पुराने हो चुके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जर्जर स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने 'उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति–2026' लागू कर दी है। नीति का मकसद 25 वर्ष या उससे अधिक पुराने भवन सुरक्षित, आधुनिक और सुविधायुक्त रूप में पुनर्विकसित करना है ताकि लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवास मिल सके।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद शहरी एवं नियोजन विभाग द्वारा अब इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।योगी सरकार की यह नीति न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन देगी, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। बेहतर नियोजन और आधुनिक डिजाइन के जरिए यह पहल उत्तर प्रदेश के शहरों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और भविष्य

के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रदेश के कई शहरों में पुराने अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं अब संरचनात्मक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। ऐसे भवनों में रहना जोखिम भरा हो गया है और महंगी शहरी जमीन का पूरा उपयोग भी नहीं हो पा रहा। नई नीति के जरिए सरकार इन पुराने और कम उपयोग किए जा रहे परिसरों को नए सिरे से विकसित कर शहरों के स्वरूप को बेहतर बनाना चाहती है। नीति के तहत वे सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स पुनर्विकास के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 25 वर्ष पुराने हैं या जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाया गया हो। हाउसिंग सोसायटी या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के मामलों में प्रक्रिया शुरू करने के लिए दो–तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। 1500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की भूमि और एकल मकान इस नीति में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा नजूल की भूमि, लीज पर आवंटित भूमि तथा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमि भी इस पुनर्विकास नीति में शामिल नहीं होगी।सरकार ने पुनर्विकास के लिए तीन मॉडल तय किए हैं। पहला, शासकीय एजेंसी द्वारा सीधे काम कराना, दूसरा पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत निजी डेवलपर की भागीदारी और तीसरा सोसायटी या एसोसिएशन द्वारा स्वयं पुनर्विकास। पीपीपी मॉडल में शासकीय अभिकरण, डेवलपर और सोसायटी के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा, जिसमें सभी की जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी। हर परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार करना अनिवार्य होगा। इसमें नए फ्लैट्स का कारपेट एरिया, पार्किंग, कॉमन एरिया, ट्रांजिट आवास या किराये की व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और तय समयसीमा जैसी जानकारियां शामिल होंगी। पुनर्विकास के दौरान जिन निवासियों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना होगा, उन्हें वैकल्पिक आवास या किराया दिया जाएगा। परियोजना को सामान्यतः तीन वर्ष में पूरा करना होगा, जबकि विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दो वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

डिप्टी सीएम ने जनता दर्शन में सुनीं जन-समस्याये

जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : केशव

संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने से पूर्व सरकारी आवास पर जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए बड़ी संख्या में लोगों ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रस्तुत कीं। उपमुख्यमंत्री ने फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना। जनता दर्शन में मुख्य रूप से भूमि विवाद, पुलिस सहायता, स्वास्थ्य उपचार हेतु आर्थिक मदद और

स्थानीय विकास कार्यों से संबंधित मामले सामने आए। अधिकारियों,डीएम, एसपी को फोन पर निर्देशित किया कि जनसमस्याओं का समाधान गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से किया जाए। सरकार जनता के द्वार है। किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन–समस्याओं का निराकरण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनता दर्शन का उद्देश्य शासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त करना है।

संक्षिप्त

लखनऊ कचहरी में बम धमकी से मचा हड़कंप, सर्च ऑपरेशन के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को उस समय हलचल मच गया जब कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं।

एहतियात के तौर पर पूरे कचहरी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। धमकी की सूचना के बाद न्यायालय परिसर, पार्किंग स्थल और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और डॉग स्क्वॉड टीम ने हर कोने की गहन जांच की। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल इलाके को घेर लिया।

विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के दलितों को साधने में जुटी भाजपा, बनाया यह प्लान

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता बरकरार रखने की कवायद में जुटी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दलित मतदाताओं को लेकर विशेष रणनीति तैयार की है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा नेताओं को बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ न बोलने की सलाह दी गई है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ क्षेत्रों में दलित वोटों के खिसकने के संकेत मिलने के बाद पार्टी ने सामाजिक समीकरणों पर नए सिरे से काम शुरू किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, भाजपा की रणनीति के केंद्र में दलित महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर व्यापक आयोजन कर समाज के विभिन्न वर्गों से सतत संवाद स्थापित करना है। पदाधिकारी ने बताया कि इसके लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें डॉक्टर भीम राव आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होल्कर समेत करीब डेढ़ दर्जन महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। उद्देश्य है कि इन आयोजनों के माध्यम से दलित समाज के बीच पार्टी की पैठ और मजबूत की जा सके। भाजपा सूत्रों की मानें तो पार्टी संगठन को निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ता दलित बस्तियों में नियमित संपर्क बनाए रखें। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद, स्थानीय स्तर पर छोटी बैठकों का आयोजन और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा मानती है कि सामाजिक इंजीनियरिंग और प्रत्यक्ष संवाद के जरिए ही 2027 में मजबूत आधार तैयार किया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ने बहुजन राजनीति की प्रमुख नेता मायावती पर सीधा हमला करने से परहेज की रणनीति अपनाई है। माना जा रहा है कि पार्टी नहीं चाहती कि दलित वोटों में किसी प्रकार की सहानुभूति की लहर पैदा हो। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमले जारी रहेंगे, लेकिन मायावती के प्रति सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरता जाएगा।

आस्था, संस्कृति और रामकथा से आलोकित हुआ राजिम कुंभ कल्प 2026

प्रख्यात कलाकार अरुण गोविल ने दी "सुनो श्री राम कहानी" की भावपूर्ण प्रस्तुति, मुख्यमंत्री से की आत्मीय भेंट

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम की पावन धरा पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 में आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। त्रिवेणी संगम के पावन तट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में सुप्रसिद्ध कलाकार एवं भगवान श्रीराम की भूमिका से जनमानस में विशेष पहचान रखने वाले अरुण गोविल ने "सुनो श्री राम कहानी" की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण परिसर भक्ति और श्रद्धा के दिव्य वातावरण से ओतप्रोत हो उठा। इस अवसर पर अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आत्मीय भेंट की तथा राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें स्मृति–चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। गोविल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनआस्था और लोगों का आत्मीय स्नेह उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आस्था, संस्कृति और पर्यटन के

संरक्षण–संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा ऐसे आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त हो रही है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, संत–महात्माओं एवं श्रद्धालुओं की गरिमामयी उपस्थिति थी। उल्लेखनीय है कि राजिम कुंभ कल्प 2026 के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित यह महोत्सव आस्था, संस्कृति और पर्यटन संवर्धन का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता अप्रैल से लागू होने की संभावना, ब्रिटिश संसद में चल रही बहस

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को समानांतर रूप से लागू करने की तैयारी चल रही है।

जुलाई में हुए समझौते के तहत भारत के 99% निर्यात ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क पर प्रवेश करेंगे। वहीं, भारत में ब्रिटिश उत्पादों, जैसे कार व स्कॉच व्हिस्की, पर आयात शुल्क में चरणबद्ध कमी की जाएगी। स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क 150% से घटाकर 75% किया जाएगा और 2035 तक इसे 40% तक लाया जाएगा। ऑटोमोबाइल पर आयात शुल्क पांच वर्षों में घटाकर 10% किया जाएगा, जो अभी 110% तक है। समझौते के तहत भारत ने चॉकलेट, बिस्कुट और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए बाजार खोला है, जबकि भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न–आभूषण, खेल सामग्री व खिलौनों को ब्रिटेन में पहुंच मिलेगी। दोहरा अंशदान संधि पर भी हैं हस्ताक्षर दोनों देशों ने दोहरा अंशदान संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अस्थायी कर्मियों को सामाजिक अंशदान दो बार नहीं देना होगा। समझौते को लागू करने से पहले ब्रिटेन की संसद की मंजूरी आवश्यक है। वहां हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस पर बहस और समीक्षा चल रही है। इसका उद्देश्य 2030 तक 56 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है।

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा दो नई कोलैटरल फ्री निर्यात ऋण योजना का शुभारंभ

बीएनई

देहरादून। निर्यात को बढ़ावा देने और भारत सरकार के विज़न के अनुरूप 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा दो नई निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है– यूनियन निर्यात सुगम और यूनियन निर्यात प्रोत्साहन योजना। यूनियन निर्यात सुगमष योजना के अंतर्गत सभी विनिर्माता निर्यातकर्ताओं को 80 करोड़ रुपये तक का निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है, जिसमें गैर–एमएसएमई भी शामिल हैं (व्यापारी, मर्चेंट निर्यातकर्ता, रत्न, आभूषण तथा हीरे और लौह अयस्क निर्यातकर्ताओं को छोड़कर). इस योजना के अंतर्गत, कोलैटरल सुरक्षा जमा करना आवश्यक नहीं है. यह योजना विशेषकर निर्यातकर्ताओं को किफ़ायती निर्यात वित्त का एक्सेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें। यूनियन निर्यात प्रोत्साहन योजनाष के अंतर्गत सभी सूक्ष्म और लघु निर्यातकर्ताओं (व्यापारी, मर्चेंट निर्यातकर्ता, रत्न, आभूषण तथा हीरे और लौह अयस्क निर्यातकर्ताओं सहित) को 10 करोड़ रुपये तक की कोलैटरल फ्री निर्यात

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

ऋण कार्यशील पूंजी दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत, कोलैटरल सुरक्षा या तृतीय पक्ष गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है. यह योजना सूक्ष्म और लघु निर्यातकर्ताओं के लिए बनाई गई है, जिसके माध्यम से किफायती और बिना किसी गारंटी के निर्यात वित्त दिया जाता है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत, रुपये और विदेशी मुद्रा में प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर दिए जाते हैं, जो बाहरी बेंचमार्क से जुड़े होते हैं और सीधा डीलिंग एक्सेस के साथ बेहतर एक्सचेंज मार्जिन देते हैं। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया सदैव विनिर्माता निर्यातकर्ताओं और एमएसएमई को सपोर्ट करने में सबसे आगे रहा है, जिसमें कार्यशील पूंजी के दबाव को कम किया गया है और निर्यातकर्ताओं और एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई तरह की ऋण सुविधाएं दी गई हैं। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निर्यात ऋण में लगभग 10% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है।

आईआईएफएल फाईनेंस ने 9 प्रतिशत सालाना रिटर्न के साथ 2,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए

बीएनई

देहरादून। देश की प्रमुख नॉन–बैंकिंग फाईनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) में से एक, आईआईएफएल फाईनेंस लिमिटेड ने रिडीमेबल नॉन–कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) के पब्लिक इश्यू जारी किए हैं, जो मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 से मिलना शुरू होंगे। इनका इश्यू साईज़ 500 करोड़ रुपये है, और 1,500 करोड़ रुपये तक का ओवरसब्सक्रिप्शन बनाए रखने के लिए ग्रीन–शू विकल्प है। इस प्रकार कुल इश्यू साईज़ 2,000 करोड़ रुपये का होगा। इस फंड का उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि करना और पूंजी बढ़ाना है। इस एनसीडी द्वारा 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक का प्रभावी रिटर्न मिलेगा और यह 24 महीनों, 36 महीनों, और 60 महीनों की अवधियों के लिए उपलब्ध होगा। ब्याज का पे–आउट मासिक, वार्षिक या मैच्योरिटी के बाद लिया जा सकता है। इस इश्यू को क्राईसिल रेटिंग्स ने क्राईसिल एए/स्टेबल रेटिंग दी

है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स द्वारा इसे बीडब्लूआर एए+ (स्टेबल) रेटिंग दी गई है, जिससे प्रदर्शित होता है कि इनमें बहुत कम क्रेडिट रिस्क है और ये फाईनेंशियल दायित्वों को समय पर पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। निर्मल जैन, फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, आईआईएफएल फाईनेंस ने कहा कि, ''आईआईएफएल फाईनेंस भारत के प्रमुख एनबीएफसी में से एक है। यह पूरे देश में मजबूत स्थिति रखता है। इसका डाईवर्सिफाईड रिटेल पोर्टफोलियो 4.6 मिलियन से अधिक वंचित ग्राहकों को क्रेडिट प्रदान करता है। इस प्रस्तावित फंड के माध्यम से हम क्रेडिट की उपलब्धता और अधिक बढ़ाएंगे तथा अपने फंडिंग स्रोतों का विस्तार करेंगे। पिछले कुछ सालों में आईआईएफएल फाईनेंस ने बॉन्ड के माध्यम से फंड एकत्रित करने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है तथा मूल राशि एवं ब्याज का समय पर भुगतान किया है।'' 31 दिसंबर, 2025 को आईआईएफएल फाईनेंस के पास 98,336 करोड़ रुपये के कंसोलिडेटेड लोन एस्सेट्स अंडर मैनेजमेंट (ए.यू.एम) थे। कंपनी लगातार मजबूत एस्सेट क्वालिटी बनाकर रखती है। 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी की कंसोलिडेटेड लोन बुक के प्रतिशत हिस्से में कंपनी के पास 1.60 प्रतिशत ग्रॉस नॉन–परफॉर्मिंग एस्सेट (एनपीए) और 0.75 प्रतिशत नेट एनपीए हैं। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी की 83.61 प्रतिशत कंसोलिडेटेड लोन बुक को पर्याप्त कोलेटरल द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था, ताकि जोखिम और कम हो जाए। वित्तवर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में आईआईएफएल फाईनेंस ने 501.3 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (पीएटी) दर्ज किया, जो सालाना 514 प्रतिशत अधिक है। वहीं वित्तवर्ष 2026 के नौ महीनों के लिए पीएटी 1,193.5 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना 265 प्रतिशत अधिक है। विभिन्न बैंकों और फाईनेंशियल संस्थानों के साथ कंपनी के मजबूत संबंध हैं, जिससे फंडिंग की रणनीति में मदद मिलती है। 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी के पास कंसोलिडेटेड आधार पर 4,761 शाखाओं का नेटवर्क था, जो देश के कोने–कोने में फैला था तथा कंपनी में कुल 36,786 कर्मचारी काम कर रहे थे। इश्यू के लीड मैनेजर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाईज़र्स प्राईवेट लिमिटेड, नुवामा वैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड हैं। निवेशकों को लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए ये एनसीडी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। हर एनसीडी की फेस वैल्यू 1,000 रुपये होगी। विभिन्न श्रेणियों में निवेशक कम से कम 10,000 रुपये के एप्लिकेशन साईज़ में आवेदन कर सकेंगे। पब्लिक इश्यू अरली क्लोज़र के विकल्प के साथ मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 को खुलेगा और बुधवार 4 मार्च, 2026 को बंद होगा। आवंटन पहले आएं, पहले पाएं के आधार पर किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति के लिए 6 जिले के 42 स्व-सहायता समूह को रेडी-टू-ईट निर्माण एवं वितरण का कार्य

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कुपोषण दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए रेडी–टू–ईट फूड निर्माण का काम महिला स्व–सहायता समूहों को सौंपते हुए 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल के तहत रायगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, और सूरजपुर जिलों में आंगनबाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार निर्माण का कार्य महिला समूहों को मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट) के निर्माण और वितरण का कार्य महिला स्वसहायता समूहों को सौंपने का फैसला किया। राज्य के 6 जिले के 42 महिला स्व–सहायता समूहों को रेडी टू ईट के निर्माण और वितरण का कार्य सौंपा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति के इस मिशन को प्रथम चरण में प्रदेश के 6 जिलों – बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ एवं सूरजपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां महिला समूहों ने 'रेडी–टू–ईट' उत्पादन प्रारंभ किया है। यह पहल महिलाओं की आर्थिक समृद्धि और बच्चों के स्वास्थ्यकृदोनों को नई दिशा प्रदान करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा–10 स्व–सहायता समूह को रेडी–टू–ईट निमाण का कार्य सौंपा जा चुका है। इसी प्रकार रायगढ़–10 स्व–सहायता समूह, सूरजपुर और बलौदाबाजार–भाठापारा जिला में 7–7 स्व– सहायता समूह को, बस्तर जिले में 6 स्व–सहायता समूह और दंतेवाड़ा में 2 महिला स्व–सहायता समूह को रेडी–टू–ईट निमाण का कार्य सौंपा जा चुका है। इन स्व–सहायता समूहों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट) का निर्माण और वितरण का कार्य किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि इन समूहों की बहनें अब आंगनबाड़ी के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ–साथ इस कार्य से अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। यह योजना महिलाओं को स्व–रोजगार के साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और परिणामोन्मुखी पहल है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बच्चों को पोषण युक्त आहार प्रदान कर राज्य के पोषण स्तर में सुधार लाने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

संक्षिप्त

PAK को भारत ने आईना दिखाया, दिल्ली के वैश्विक मंच पर पड़ोसी को जगह नहीं; मायने क्या?

दिल्ली ब्यूरो

दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया–एआई इंपैक्ट समिट 2026 में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब पांच बजे इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वैश्विक कंपनियों और राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को रेखांकित करेंगे। पीएम मोदी नीत सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रति भारत सख्त नीतियां अपना रहा है, एआई इंपैक्ट समिट में न्योता न भेजना इसकी एक और बानगी है। दिल्ली में हो रहे इस पांच दिवसीय ग्लोबल इवेंट में किन राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है? किन देशों की कौन सी बड़ी कंपनियां

भारत में एआई से जुड़े इस आयोजन में भाग ले रही हैं? पीएम मोदी नीत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या नीतियां अपना रही है? बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्यों के बीच भारत का ये प्रयास सही मायने में वैश्विक क्यों है? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस खबर में पाकिस्तान को नहीं दिया गया निमंत्रण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा समेत कई प्रमुख वैश्विक नेता इस समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट के लिए पाकिस्तान को आमंत्रण न दिए जाने को लेकर आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस समिट के लिए अब तक लगभग तीन लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। सम्मेलन का मकसद केवल तकनीकी विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि एआई को हेल्थकेयर, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लागू कर आम लोगों के जीवन में वास्तविक और व्यापक सुधार लाना भी है।

26 में जिले को बालश्रम मुक्त कराने निकला रथ, डीएम ने किया रवाना

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। जनपद को 2026 तक बाल श्रम मुक्त कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से बाल श्रम जनजागरण रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि बाल श्रम समाप्त करने के लिए सभी बच्च्यों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने के रणनीति बनाकर कार्य करना होगा। इस दौरान श्रम विभाग और एसोसिएशन फॉर वालेटरी एक्शन द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी ने कहा कि सभी को बाल श्रम के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हम लोगो का अपनी सोच इस सीमा तक बदलनी होगी कि इसका असर या परिणाम हमारे व्यवहार पर दिखने लग जाये एवं हमारे दिमाग में स्थापति हो जाये कि ये जो हम कर रहे हे जो हमे सुविधाजनक सा लगता है वह वास्तव में एक अपराध है जो समाज के प्रति एवं उस बच्चे के प्रति एवं बच्चे के परिवार के प्रति अपराध है। बाल श्रम के प्रति इसमें प्रचार प्रसार की भी जरुरत होगी। बाल श्रम सभी लोगो के समेकित प्रयास से खत्म कराना होगा। श्रम विभाग के राज्य समन्वयक सैयद रिजवान अली द्वारा कार्यशाला का विस्तृत विवरण साझा किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जनपदों को बाल श्रम मुक्त तथा चयनित आकांक्षी जनपदों को दिसंबर 2026 तक बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। अली द्वारा विशेष रूप से कन्नौज जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने हेतु

सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वयए संयुक्त कार्यवाही एवं एक मंच पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही कन्नौज के समस्त ईंट भट्टोंए में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण कराए जाने का अनुरोध भी किया। इस अवसर पर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन से कार्यक्रम समन्वयक अमरेंद्र कुमार व राष्ट्रीय प्रशिक्षक अभय अवस्थी द्वारा संस्था का परिचय दिया गया तथा उसके मिशन एवं विजन पर चर्चा की। साथ ही कन्नौज जनपद में बाल श्रम के प्रति रणनिति बनाकर कार्य करने हेतु सम्बन्धित से अपेक्षित सहयोग लेकर बाल श्रम पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया गया और श्रम विभाग के साथ कन्वर्जेस कर बाल श्रम मुक्त कन्नौज बनाने हेतु मिलकर कार्य करने पर विशेष जोर दिया। उनके द्वारा कानून को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु चर्चा की गई जिससे बाल श्रम को रोका जाये उनके द्वारा संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों के वारे में विस्तार से जानकारी दी । उन्होने ने सभी संगठनों से बाल श्रम को खत्म करने के लिये सभी से सहयोग की अपेक्षा की । इस अवसर राज्य समन्वयक सैय्यद रिजवान अली श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, स्टेट को–ऑर्डिनेटर, ए०वी०ए० अमरेंद्र कुमार , राष्ट्रीय प्रशिक्षक अभय अवस्थी, नवनीत कुमार श्रीवास्तव श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जीशान अन्सारी जिला समन्वय ए०वी०ए० इत्यादि उपस्थित रहें।

वित्त मंत्री सीतारमण आधिकारिक दौरे पर नॉर्वे पहुंचीं, जानें RBI के नए नियमों में किस पर फोकस

एजेंसी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि ओस्लो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारत की नॉर्वे में राजदूत ग्लोरिया गांगटे ने उनका स्वागत किया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे पर आगमन पर भारतीय राजदूत द्वारा औपचारिक स्वागत किया गया। इस

दौरे को भारत–नॉर्वे आर्थिक सहयोग, निवेश संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। RBI के नए नियमों से एमएंडए फंडिंग को बढ़ावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंकों की कैपिटल मार्केट एक्सपोजर (CME) से जुड़े नए नियमों से अब लेंडर्स कॉरपोरेट टेकओवर, मर्जर एंड एक्विजिशन (M–A) और लेवरेज्ड बायआउट जैसे सौदों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के अनुसार, यह नया फ्रेमवर्क बैंकों को अधिग्रहण से जुड़े डील्स को फंड करने की अनुमति देता है, साथ ही जोखिम पर कड़ा नियंत्रण भी सुनिश्चित करता है।

महिला केंद्रित और क्वीर फिल्में बनाना चाहती हैं श्वेता त्रिपाठी, बोलीं– 'यह मेरे लिए घर जैसा'

एजेंसी

'मिर्जापुर' वेब सीरीज में गोलू का किरदार निभाकर सुर्खियां बटोरने वाली अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी अब प्रोड्यूसर बन गई हैं। उन्होंने महिला प्रधान कहानियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्माण क्षेत्र में कदम रखा है। उनका मानना है कि यह उनके लिए सही है, घर जैसा है और एक कलाकार के रूप में उनके व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है। श्वेता बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म की घोषणा भी कर चुकी हैं। इसके अलावा वो क्वीर फिल्मों पर भी ध्यान दे रही हैं। हमें खुद बदलाव का हिस्सा बनना होगा क्वीर फिल्मों व महिला केंद्रित फिल्मों को लेकर श्वेता ने कहा कि अगर हम किसी तरह का बदलाव देखना चाहते हैं, तो हमें खुद उसका हिस्सा बनना होगा। महिलाओं और क्वीर जीवन की कहानियां हमेशा से मौजूद रही हैं, लेकिन उन्हें हमेशा वह स्थान और सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। अगर मुझे अब चुनने और फिल्में बनाने का सौभाग्य मिला है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं इसका उपयोग कैसे करती हूं। कभी–कभी ये कहानियां कोमल और रोजमर्रा की होती हैं। वे हमेशा खुद को जाहिर नहीं करतीं, लेकिन वे आपके साथ रह जाती हैं। मैं इसी तरह के काम से जुड़ना चाहती हूं। श्वेता चाहती हैं कि ये कहानियां मानवीय, त्रुटिपूर्ण और जानी–पहचानी सी लगें। यही सोच उन समलैंगिक कहानियों पर भी लागू होती है, जिनका वह समर्थन करती हैं। मैं इसी रास्ते पर चलना चाहती हूं अभिनेत्री ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यही वह रास्ता है जिस पर मैं चलना चाहती हूं। महिलाओं द्वारा निर्देशित विषयों का समर्थन करना, समलैंगिक आवाजों को बढ़ावा देना और अपने फैसलों में ईमानदार रहना। यह सही लगता है और मुझे घर जैसा महसूस होता है। साथ ही एक कलाकार के रूप में यह मेरे लिए एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा भी है। 'मिर्जापुर : द मूवी' में नजर आएंगी श्वेता वर्कफ्रंट की बात करें तो श्वेता त्रिपाठी अब 'मिर्जापुररू द मूवी' में नजर आएंगी। वेब सीरीज के तीन सीजन आने के बाद अब मेकर्स मिर्जापुर पर एक फिल्म बना रहे हैं। यह फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सीरीज के मुख्य कलाकारों के साथ कुछ नए कलाकार भी शामिल हुए हैं। इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, रसिका दुग्गल, हर्षिता गौर समेत जितेंद्र कुमार और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743